

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2294
दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक जलवायु कूटनीति मंचों में भारत

2294. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वैश्विक जलवायु कूटनीति मंचों में भारत के नेतृत्व वाली हालिया पहलों के ब्यौरे सहित 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा भागीदारी के आरंभ से संबंधित आंकड़े क्या हैं;
- (ख) सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु अनुकूलन के संबंध में ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग सुदृढ़ करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) जलवायु संबंधी कार्रवाई में भारत के वैश्विक नेतृत्व को सुदृढ़ करने हेतु भारत के कूटनीतिक प्रयासों ने विकासशील देशों हेतु जलवायु वित्तपोषण जुटाने एवं प्रौद्योगिकी में अंतरण किस प्रकार योगदान दिया है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क से ग) जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सामूहिक कार्रवाई समस्या है और इसके समाधान हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसीसी) और पेरिस समझौते का एक पक्षकार है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्रवाई में यूएनएफसीसीसीसी के सिद्धांतों, विशेष रूप से, राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में इक्विटी और सामान्य परंतु विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है।

भारत वैश्विक जलवायु कार्रवाई में सबसे आगे रहा है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पहलों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और इसका नेतृत्व कर रहा है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड, आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन, द्वीप राज्यों के लिए अनुकूल अवसंरचना, उद्योग संबंधी परिवर्तन हेतु नेतृत्व समूह, हरित ऋण पहल, मिशन नवाचार और मिशन लाइफ शामिल हैं।

विकास सहयोग, साझेदार देशों के साथ भारत के जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। भारत सरकार ने, ग्लोबल साउथ के साथ अपने जुड़ाव के हिस्से के रूप में, कई विकास परियोजनाएं शुरू की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, सतत विकास लक्ष्यों एवं जलवायु अनुकूलता पर ध्यान केंद्रित किया है। विकास संबंधी सहायता मुख्य रूप से लाइन्स ऑफ़ क्रेडिट (एलओसी), रियायती वित्त योजना (सीएफएस) और सहायता अनुदान परियोजनाओं पर दी जाती है।

भारत यूएनएफसीसीसीसी में जलवायु वार्ताओं में रचनात्मक भूमिका निभा रहा है और विकसित देश वाले से विकासशील देश वाले पक्षकारों तक जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी को जुटाने का समर्थन कर रहा है। भारत ने लगातार नए, अतिरिक्त और रियायती जलवायु वित्त को आवश्यक पैमाने पर बढ़ाने की मांग की है, साथ ही इस बात पर बल दिया है कि जलवायु प्रौद्योगिकियों को सुलभ, किफायती और प्रतिबंधात्मक बौद्धिक संपदा बाधाओं से मुक्त होना चाहिए।
